विशेष: गिलगित-बाल्टिस्तान: पाकिस्तान की नापाक कोशिश और भारत का विरोध

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खाकान अब्बासी ने एक शासकीय ऑर्डर जारी कर गिलगित-बाल्टिस्तान स्वायत्तशासी क्षेत्र के प्रशासन के सभी अधिकार समाप्त कर दिये। गिलगित-बाल्टिस्तान स्वायत्तशासी क्षेत्र के अधिकारों को सीमित करने के पीछे माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इसे अपना पाँचवां प्रांत बनाने जा रहा है। भारत ने कड़ा विरोध करते हुए इसे गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मिलाने की साजिश बताया और कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गिलगित-बाल्टिस्तान उसी प्रांत का एक हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहे इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनधिकृत तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है।

क्या है इस आदेश में?

- पाकिस्तान की कैबिनेट ने 21 मई को गिलगित-बाल्टिस्तान संबंधी आदेश को मंज़ूरी दी थी और क्षेत्र की विधानसभा ने भी इसका समर्थन किया।
- गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) ऑर्डर 2018 के आर्टिकिल 77(2) के मुताबिक, गिलगित-बाल्टिस्तान की अदालतों के पास अब न तो इतनी शक्ति है और न ही क्षमता कि वे देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकें। इस आर्टिकिल के तहत प्रधानमंत्री को कानून से भी ऊपर रखा गया है।
- नए कानून ने 'गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश 2009' का स्थान लिया है, जिसके तहत गिलगित-बाल्टिस्तान की स्थानीय परिषद खनिज, जलविद्युत और पर्यटन से संबंधित कानून बनाती थी और इस पर फैसला लेती थी।
- अब ये फैसले गिलगित-बाल्टिस्तान की विधानसभा लेगी।
- नए कानून के तहत अब इस इलाके के लोगों को पाकिस्तान के अन्य चार प्रांतों की तरह अधिकार हासिल होंगे।

अभी क्या है स्थिति?

- बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के चार प्रांत हैं।
- पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों अलग-अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा मानता है।
- इन दोनों क्षेत्रों की अपनी विधानसभाएँ हैं और तकनीकी रूप से यह पाकिस्तान संघ का हिस्सा नहीं है।
- पाकिस्तान कश्मीर के लिये एक विशेष मंत्री और संयुक्त परिषदों के ज़रिये उनका शासन करता है।
- प्रत्यक्षतः दोनों क्षेत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन विदेश और रक्षा मामले पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं।
- अभी तक गिलगित-बाल्टिस्तान स्वायत्त क्षेत्र है, जहाँ प्रादेशिक असेंबली के अलावा एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है।
- इसका कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किमी. है और इसका प्रशासनिक केंद्र गिलगित शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग ढाई लाख है।
- कुल लगभग 20 लाख की जनसंख्या में 14% शहरी आबादी वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में शिया मुस्लिमों की संख्या अधिक है।
- पाकिस्तान ने 1963 में पाक अधिकृत कश्मीर की 5 हजार वर्गमील वाली शक्सगाम घाटी का इलाका चीन को दे दिया था, जिससे होकर चीन ने काराकोरम राजमार्ग बना लिया।
- 1970 में पाकिस्तान ने गिलगित एजेंसी, बाल्टिस्तान, हुंजा और नगर इलाकों को मिलाकर नार्दन एरियाज़ का गठन किया था।
- गिलगित-बाल्टिस्तान में कुल 7 ज़िले हैं, जिनमें से 5 गिलगित में और 2 बाल्टिस्तान में हैं तथा गिलगित और स्कर्दू से इनका प्रशासन चलाया जाता है।
- पाकिस्तान ने एक योजना के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश जारी कर 2009 में गिलगित-बाल्टिस्तान में विधानसभा बनाई थी, ताकि इस क्षेत्र को अलग प्रांत बनाया जा सके।
- गिलगित-बाल्टिस्तान की सीमाएँ पश्चिम में खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, उत्तर-पूर्व में चीन के शिन्जियांग प्रांत से, दक्षिण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दक्षिण-पूर्व में भारतीय जम्मू-कश्मीर राज्य से लगती हैं।

क्यों बनाना चाहता है पाँचवां प्रांत?

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है। चूँकि यह इलाका विवादित है, इसलिये चीन चाहता है कि इस कॉरीडोर के तैयार होने से पहले इसके तमाम कानूनी पहलू पूरे कर लिये जाएँ। अगर गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के पाँचवें प्रांत का दर्जा दिया जाता है तो भारत के लिये परेशानी यह होगी कि पाकिस्तान कानूनी तौर पर इस इलाके पर अपना दावा मज़बूत कर लेगा और चीनी सेना की यहाँ मौजूदगी भी हो जाएगी।

भारत की चिंता

- यह इलाका पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर (PoK) से लगा हुआ है और अपनी भौगोलकि स्थतिकी वज़ह से भारत के लयि सामरकि दृष्टसे बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इसके पश्चमि में पाकस्तिान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, उत्तर में चीन और अफगानस्तिान तथा पूर्व में भारत है, जसिमें दुनयि का सबसे ऊँचा युद्धस्थल और क्षेत्र में सामरकि रूप से महत्त्वपूर्ण सयिाचनि भी शामलि है।
- भारत इस ववािदति क्षेत्र से CPEC के गुजरने को लेकर चीन के समक्ष कई बार वरिोध दर्ज करा चुका है।
- पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर की सीमा से लगे गलिगति-बाल्टस्तिान क्षेत्र को पाँचवां प्रांत घोषति करने की पाकस्तिान की कसिी भी कोशशि को भारत नकारता है।
- भारत पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभन्नि अंग मानता है जसिमें पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर और गलिगति-बाल्टस्तिान दोनों आते हैं, इसलयि पाकस्तिान को जम्मू-कश्मीर के कसिी भी हस्सि को एक अलग पाकस्तिानी प्रांत बनाने का कोई अधकिार नहीं है।

पाकस्तिान के लयि ज़रूरी है CPEC

- अप्रैल 2015 में चीन और पाकस्तिान के बीच इस बहुचर्चति गलयिारे को लेकर समझौता हुआ था। इस गलयिारे से चीन को हदि महासागर में प्रवेश करने का मौका मलि गया है।
- इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चमि एशयि में अपना राजनैतकि और सैनकि प्रभुत्व बनाए रखने के लयि एक उपनविश स्थापति कर लयि है।
- चीन-पाकस्तिान के इस आर्थकि गलयिारे ने पारंपरकि उत्तर-दक्षणि व्यापार पथ को पलटकर रख दयि है।
- पाकस्तिान ने ऐसे आर्थकि और भौगोलकि मार्ग को चुना है, जसिका नक्शा अब चीन तय करता रहेगा।

क्या है CPEC?

- चीन के सहयोग से 51 बलियिन डॉलर की लागत वाली इस परयिोजना पर तेज़ी से काम चल रहा है।
- इसका उद्देश्य पाकस्तिानी अवसंरचना को बढ़ाना और उसे समुन्नत करना है तथा साथ ही पाकस्तिान और चीन के बीच आर्थकि संबंधों को और मज़बूत करना भी है।
- यह परयिोजना दक्षणि-पश्चमि में पाकस्तिान के ग्वादर को चीन के उत्तर-पश्चमि के शनिजयिांग प्रांत से एक राजमार्ग और रेलवे के वृहत् नेटवर्क से जोड़ेगी।
- इस परयिोजना के तहत 1,100 कलिोमीटर का लंबा राजमार्ग कराची और लाहौर के बीच में बनाया जाएगा।

कराकोरम हाईवे: इसके अलावा रावलपडिी और चीनी सीमा के बीच कराकोरम हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर के गलिगति-बाल्टस्तिान क्षेत्र के हुंजा इलाके में एक गाँव है सुस्त, जो चीनी सीमा के पहले कराकोरम राजमार्ग पर अंतमि गाँव है। यहीं से चीन के मालवाहक कंटेनर कराकोरम हाईवे से होकर गलिगति-बाल्टस्तिान में प्रवेश करेंगे।

- CPEC के तहत पाकस्तिान के रेल नेटवर्क को चीन के दक्षणिी शनिजयिांग रेलवे, काशगर से जोड़ा जाएगा।
- प्राकृतकि गैस और अन्य पेट्रोलयिम पदार्थों के परविहन के लयि पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क भी इस परयिोजना के तहत बनाया जाएगा।
- इसमें 2.5 बलियिन डॉलर की लागत से ग्वादर और नवाबशाह के बीच बनने वाली पाइपलाइन भी शामलि है जसिे ईरान से आने वाली गैस को लाने के लयि बनाया जाएगा।
- चीन द्वारा बनाया जा रहा यह कॉरीडोर गलिगटि-बाल्टस्तिान और पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर से होकर गुजरेगा।
- पाकस्तिान के अनुसार इस परयिोजना से 2015-2030 के बीच 7 लाख रोज़गार उत्पन्न होंगे।
- इससे पाकस्तिान के आर्थकि वकिास में 2 से 2.5 प्रतशित वार्षकि की वृद्धि हो सकती है।
- चीन का यह नविेश 2002 से अब तक पाकस्तिान को अमेरकिा से मलिी कुल आर्थकि सहायता से भी ज़्यादा है।

(टीम दृष्टइिनपुट)

चीन के कब्ज़े वाला अक्साई चनि भी जम्मू-कश्मीर का हस्सिा है

- भारत और चीन के बीच एक लंबी सीमा है और इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा भारत के लयि हमेशा से एक जटलि मुद्दा रहा है। कभी-कभी इस क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा अतक्रिमण की खबरें भी आती रहती हैं।
- जम्मू-कश्मीर में चीन के साथ भारत का ववािद अक्साई चनि क्षेत्र को लेकर रहता है। इसे भारत जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का हस्सिा मानता है, जबकि इस पर वास्तवकि नयिंत्रण चीन का है और यह उसके स्वायत्तशासी प्रांत शनिजयिांग का हस्सिा है।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने तत्कालीन 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटयिर एजेंसी' (NEFA) के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लयि था और चीनी सेना तेज़पुर तक पहुँच गई थी।
- 21 नवंबर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धवरिाम लागू करके पूरे पश्चमिी अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली और इस क्षेत्र में युद्ध से पूर्व की स्थतिि को बहाल कर दयि था।
- चीन ने लद्दाख के जसि क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लयि था, उसे अपने नयिंत्रण में बनाए रखा, जो आज भी चीन के नयिंत्रण में है। इसी क्षेत्र को अक्साई चनि (Aksai Chin) कहते हैं।
- भारत का कहना है कि चीन ने 1962 की लड़ाई में अक्साई चनि के 38 हज़ार वर्गमील इलाके पर कब्ज़ा कर लयि था।

अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या है कहना?

- गलिगति-बाल्टस्तिान पर पाकस्तिान का कब्ज़ा पूरी तरह अवैध है; न केवल ब्रटिशि संसद इसे कश्मीर का हस्सिा मानती है, बल्कि यूरोपीय संघ भी इसे कश्मीर का ही हस्सिा बताता है।
- ब्रटिेन की संसद में पछिले वर्ष कंज़र्वेटवि संसद बॉब ब्लैकमैन ने एक प्रस्ताव रखा था जसिमें गलिगति-बाल्टस्तिान पर पाकस्तिान के कब्ज़े को अवैध बताया गया था।
- इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकस्तिान ने गलिगति-बाल्टस्तिान पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है, जबकि यह क्षेत्र उसका है ही नहीं।

क्या है इस क्षेत्र का इतहिास?

- पहले इसे उत्तरी (शुमाली) इलाका अर्थात् नॉर्दन एरयिाज़ कहा जाता था। अपनी भौगोलकि संरचना की वज़ह से यह इलाका भारत, चीन और पाकस्तिान, तीनों के लयि सामरकि दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है।

वविादति लीज़ डीड: डोगरा शासकों ने अंग्रेजों के साथ हुई लीज़ डीड को 1 अगस्त, 1947 को रद्द करते हुए क्षेत्र पर अपना नयिंत्रण कायम कर लयि। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सहि ने 1935 में एक लीज़ डीड के तहत ब्रटिशि शासकों को 60 साल तक के लयि इस क्षेत्र का नयिंत्रण दे दयि था।

- 1947 में भारत वभिाजन के समय यह क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर की तरह न भारत का हस्सिा रहा और न ही पाकस्तिान का।
- महाराजा हरि सहि को गलिगिति स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मरि्जा हसन खान के वद्रिोह का सामना करना पड़ा, जसिने 2 नवंबर, 1947 को गलिगति-बाल्टस्तिान की आजादी का ऐलान कर दयि।
- इससे दो दनि पहले 31 अक्तूबर को कश्मीर के महाराजा ने रयिासत के भारत में वलिय को मंजूरी दी थी।
- 21 दनि बाद पाकस्तिान इस क्षेत्र में दाखलि हुआ और उसने सैन्य बलों तथा कबाइलयिों के बल पर इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लयि।
- अप्रैल 1949 तक यह इलाका पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर का हस्सिा माना जाता रहा।
- 28 अप्रैल, 1949 को पाकस्तिान अधकिृत कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जसिके तहत गलिगति के मामलों को सीधे पाकस्तिान की केंद्र सरकार के तहत कर दयि गया।
- इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है और क्षेत्र का कोई भी नेता इस करार में शामलि नहीं था।
- वविादति गलिगति-बाल्टस्तिान में दो स्वतंत्रता दविस मनाए जाते हैं--एक 14 अगस्त को, जब पाकस्तिान अपना स्वतंत्रता दविस मनाता है और दूसरा 1 नवंबर को, जब यह इलाका 1947 में हासलि की गई अपनी उस आज़ादी को याद करता है, जो केवल 21 दनि तक टकि पाई थी।
- कालांतर में पाकस्तिान ने गलिगति-बाल्टस्तिान के सुदूर उत्तर में स्थति एक इलाके को कराकोरम राजमार्ग के नरि्माण के लयि चीन को दे दयि।
- पाकस्तिान का कहना है कि डोगरा राजतंत्र ने क्षेत्र पर नयिंत्रण को खत्म कर दयि था और जम्मू-कश्मीर के अंतमि राजा महाराजा हरि सहि का लगभग 73 हज़ार वर्ग कलिोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर कोई अधकिार नहीं था। लेकनि ऐसे में सवाल उठता है कि पाकस्तिान को इस क्षेत्र का नयिंत्रण कैसे मलि गया?
- पाकस्तिान भारत के इस दावे को यह कहकर नकारता है कि डोगरा शासकों ने 1846 में इस इलाके को जम्मू-कश्मीर में शामलि कर लयि था, अन्यथा यह कभी भी इस रयिासत का हस्सिा नहीं रहा।
- अपने दावे के पक्ष में पाकस्तिान 1935 की उपरोक्त लीज़ डीड का उल्लेख करता है, जसिने ब्रटिशि शासकों को 60 साल तक के लयि इस क्षेत्र का नयिंत्रण दे दयि था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नष्किर्ष: भारत का दावा है कि गलिगति-बाल्टस्तिान 1947 तक अस्तत्वि में रही जम्मू-कश्मीर रयिासत का हस्सिा रहा था, इसलयि यह पाकस्तिान के साथ क्षेत्रीय वविाद का हस्सिा है। पाकस्तिान इस क्षेत्र को वविादति कश्मीर के क्षेत्र से पृथक मानता है और इस पर अपने कब्ज़े के बाद उसने चीन के सहयोग से इस क्षेत्र के खनजिों और जलवद्युत संसाधनों के दोहन के लयि बड़े पैमाने पर नविेश कयि है। चीन के साथ मलिकर पाकस्तिान यहाँ आर्थकि कॉरीडोर तथा अन्य बड़ी परयिोजनाओं पर काम कर रहा है। इस वविादति क्षेत्र में चीन की पहुँच और पाकस्तिान के दमनकारी शासन के मानवाधकिार उल्लंघन ने इलाके में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दयि, लेकनि इस आंदोलन की कम ही जानकारी मलिती है। बेहद कड़े संघीय कानून इस क्षेत्र तक वदिेशयिों और मीडयि की पहुँच को लगभग असंभव बनाते रहे हैं। जब भी पाकस्तिान और चीन की गतविधियिों का यहाँ के लोग वरिोध करते हैं तो सेना इसे कुचल देती है। स्थानीय लोग इसका वरिोध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकस्तिान का उद्देश्य क्षेत्र के जनसांख्यकिीय चरत्रि को बदलना है। यहाँ के स्थानीय नविासी चाहते हैं कि भारत और पाकस्तिान के बीच कश्मीर वविाद के हल की प्रक्रयिा में उन्हें भी हस्सिा बनाया जाए।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gilgit-baltistan